However, from any special jurisdictional considerations, a division can also have 3 sub-divisions instead of the usual 4 sub-divisions.

(e) A case for creation of Electrical divisions/Sub-divisions is under consideration. One division, if found justified, is expected to be located at Bhubneswar.

(f) Does not arise.

राजस्थान को 1981–82 के दौरान सप्लाई की जाने वाली विद्युत की मात्रा

2630. **श्री विरदा राम फुलवारिया :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष 1981–82 के दौरान विभिन्न राज्यों से राजस्थान राज्य को कितने मेगावाट विद्युत की सप्लाई किए जाने की संभावना है ; और

(ख) विद्युत के मामले में राजस्थान कब तक आत्म-निर्भर हो जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जब राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र के दोनों यूनिट कार्य कर रहे होते हैं और भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड, चम्बल आदि जैसे अन्य स्रोतों से सप्लाई उपलब्ध होती रहती है तब राजस्थान कुल मिलाकर अपनी विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ होता है। तथापि, राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र की एक या दोनों यूनिटों की बन्दी के दौरान या अन्य स्रोतों से सप्लाई में कमी होने पर, राजस्थान को इन अवधियों के दौरान विद्युत की कमी का सामना करना पड़ता है। चूंकि राजस्थान के पड़ोसी राज्य भी इस वर्ष के दौरान विद्युत की कमी की स्थिति का सामना कर रहे हैं, राजस्थान को पर्याप्त व्यस्ततमकालीन सहायता देना संभव नहीं हुआ है। यद्यपि, इस राज्य को विभिन्न अवसरों पर भाखड़ा-व्यास प्रबन्ध बोर्ड तथा बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से सहायता दी गई है। आशा है कि केन्द्रीय क्षेत्र के बदरपुर/बैरास्यूल विद्युत केन्द्रों से मार्च, 1982 से कुछ व्यस्ततमकालीन सहायता दे सकना संभव हो जाएगा। जहां तक क्षेत्र के अन्य राज्यों से व्यस्ततमकालीन सहायता का संबंध है यह बात समय-समय इन राज्यों में अपनी-अपनी विद्युत सप्लाई की स्थिति पर निर्भर करेगी। देश में प्रचुर विद्युत उपलब्ध कराने की संकल्पना है। फालतू बिजली वाले क्षेत्रों से कमी वाले राज्यों में बिजली पहुंचाई जा सकती है। यदि योजना लक्ष्यों को पूरा कर लिया जाता है तो राजस्थान की आवश्यकताएं पूर्णतः पूरी हो जाएंगी।

Generating Capacity in West Bengal

2631. SHRI NIREN GHOSH: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the suggestion by the Electricity Enquiry Commission set up by the Calcutta High Court that new plants with a total generating capaicty of 1700 MW should be set up in West Bengal;

(b) whether want of new 17 MW would create chaotic conditions at the end of the decade;

(c) if so, whether the Union Government are considering the matter; and

(d) if so, has any plan or project been drawn up?